भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1845
जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।
22 माघ, 1947 (शक)

नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन

1845. डॉ. नामदेव किरसानः
श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, कितने स्वीकृत हुए हैं और कितने निवेश की व्यवस्था की गई है;
(ख) क्या नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) की मानकीकृत परिणामी केपीआई की अनुपलब्धता से संबंधित हालिया रिपोर्ट के आलोक में परिणामी प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों (केपीआई) को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो केपीआई सूची और बेसलाइनों का ब्यौरा क्या है;
(ग) गतिशक्ति मानदंडों का उपयोग करते हुए नियोजित और कार्यान्वित की गई सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं (स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ियों) की मंत्रालय-वार और राज्य-वार सूची का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने उन विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान की है जो भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृति संबंधी बाधाओं के कारण अपनी मूल समय-सीमा से आगे बढ़ गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) डिजिटल इंडिया और संबंधित ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों/विभागों अथवा राज्यों द्वारा तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय परिभाषित प्रदर्शन, सेवा वितरण और अपनाने के मेट्रिक्स के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी करता है। मानकीकृत प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) संबंधित डिजिटल इंडिया पहलों की प्रकृति, पैमाने और उद्देश्यों के आधार पर परियोजना-वार विकसित किए जाते हैं। इन केपीआई में मोटे तौर पर सेवा उपलब्धता, उपयोगकर्ता अंगीकरण, लेनदेन की मात्रा, सेवा वितरण समयसीमा, उपयोगकर्ता संतुष्टि, मापनीयता और सुरक्षा अनुपालन जैसे पैरामीटर शामिल हैं।

इसके अलावा, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) का उपयोग विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा किया जाता है, जो नीति आयोग का एक संबद्ध कार्यालय है, जो विभिन्न योजनाओं/परियोजना/प्लेटफॉर्म स्तर पर सरकारी मंत्रालयों में आउटपुट-आउटकम संकेतकों की निगरानी करता है।

केंद्रीय मंत्रालय और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी वगैरह जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सहित अपने-अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और उन्हें पूरा करने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) - एक जियोस्पेशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म - का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पीएमजीएस एनएमपी के तहत, जिला मास्टर प्लान (डीएमपी) की पहल अस्पताल, स्कूल, आंगनवाड़ी आदि जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए योजना बनाने पर केंद्रित है। डीएमपी पहल को सभी 112 आकांक्षी जिलों के लिए सुलभ बनाया गया है।

बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक संस्थागत तंत्र यानी परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की स्थापना की गई है। पीएमजी परियोजनाओं की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-मंत्रालयी और अंतर-राज्य समन्वय तंत्र के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी से संबंधित मामलों सहित नियामक मुद्दों के समाधान में सहायता करता है।

*****